Publication Name: The Indian Express
Publication Date: 26/02/2026
Edition: Delhi
Page No: 18
CCM: 555.68

BHARAT TAXI is India's first cooperative-led ride-hailing platform registered under the Multi-State Cooperative Societies Act, 2002. Home & Cooperation Minister Amit Shah officially launched India's first cooperative-based ride-hailing platform, Bharat Taxi, in New Delhi recently. On this occasion, 9 MoU were exchanged with key public & private stakeholders to strengthen operational integration, digital empowerment, safety, and service delivery. Vivek Pandya, CEO, Bharat Taxi, has described Bharat Taxi as the world's first mobility cooperative.

Publication Name: The Hindu
Publication Date: 26/02/2026
Edition: Vijayawada
Page No: 4
CCM: 63.01

₹504 crore to be spent to set up 1,005 warehouses

The Hindu Bureau
VIJAYAWADA

The State is strengthening its farm storage network with the development of 1,005 modern warehouses under the Centre's Agriculture Infrastructure Fund (AIF) at an investment of ₹504.42 crore, Agriculture Minister K. Atchannaidu informed the Council on Wednesday.

Launched in June 2020, the programme aims to upgrade Primary Agricultural Cooperative Societies (PACS) into Multi-Purpose Facilitation Centres (MPFCs) equipped with scientific warehousing and drying yards. the 1,005 warehouses sanctioned, 717 have been completed along with drying platforms.

Publication Name: Dainik Jagran
Publication Date: 26/02/2026
Edition: Dehradun
Page No: 3
CCM: 70.41

Loan of 21 crore rupees distributed in cooperative fairs

सहकारिता मेलों में वितरित किया गया 21 करोड़ रुपये का ऋण

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून : अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, 2025 के अवसर पर प्रदेशभर में आयोजित सहकारिता मेलों के माध्यम से किसानों, काश्तकारों, युवा उद्यमियों और महिला स्वयं सहायता समूहों को 21 करोड़ रुपये से अधिक का ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया गया है।

सहकारिता मंत्री डा. धन सिंह रावत ने बताया कि इन मेलों के जरिए अब तक 1038 किसानों और 147 महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण का लाभ मिला है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 11 जनपदों में सहकारिता मेलों का सफल आयोजन किया जा चुका है, जबकि टिहरी में भी मेला आयोजित किया गया। जनपदवार ऋण वितरण में अल्मोड़ा में 1.74 करोड़, बागेश्वर में 1.15 करोड़, पिथौरागढ़ में 2.11 करोड़, चंपावत में 81 लाख, नैनीताल में 1.07 करोड़, चमोली 1.55 लाख, रुद्रप्रयाग में 1.77 लाख, पौड़ी में 5.83 करोड़, हरिद्वार में 71 लाख, देहरादून में 98 लाख और उत्तरकाशी में 56 लाख रुपये वितरित किए गए हैं।

Publication Name: Dainik Jagran
Publication Date: 26/02/2026
Edition: Patna
Page No: 13
CCM: 313.15

Gujarat's successful cooperative societies model to be implemented

राजधानी जागरण

गुजरात की सफल सहकारी समितियों का माडल होगा लागू

दीनानाथ साहनी ● जागरण

पटना : सहकारिता विभाग द्वारा गुजरात में सफल सहकारी समितियों के माडल को लागू कराने की तैयारी हो रही है। इसके लिए विभागीय स्तर से सहकारी समितियों के 50-50 लोगों की टीम गुजरात के दौरे पर भेजी जाएगी। ये टीमें गुजरात में कार्यरत सहकारी समितियों के कार्यों का अवलोकन और अध्ययन करेंगी। बिहार में 28 हजार सहकारी समितियां हैं जिनके अध्यक्षों व सचिवों के अलावा सदस्यों की अलग-अलग टीम बनाकर गुजरात भेजी जाएगी। वहां से लौटने के बाद संबंधित सहकारी समितियों को गुजरात में कार्यरत समितियों की तरह कार्य करने हेतु प्रेरित किया जाएगा।

हाल में गुजरात में कोआपरेटिव कान्फ्रेंस में शामिल होकर लौटे सहकारिता मंत्री डा. प्रमोद कुमार ने बताया कि गुजरात में सामूहिक जैविक खेती का नवाचार सफल माडल साबित हुआ है। गुजरात में सहकारी समितियां किसानों को सीधे जोड़कर, उन्हें जैविक खेती का प्रशिक्षण, प्रमाणित जैविक इनपुट (बीज, खाद) और उत्पाद की अच्छी मार्केटिंग सुनिश्चित करके जैविक खेती को बढ़ावा दे रही हैं। भारत आर्गेनिक जैसी संस्थाएं और डेयरी, गोबर से खाद बनाकर और फसलों की जैविक खरीद-बिक्री के लिए जीयूजेको और अमूल जैसे नेटवर्क का उपयोग करती हैं। जब गुजरात से ऐसी सहकारी समितियों का कार्यानुभव लेकर टीम लौटेगी तब जैविक खेती में गुजरात माडल का सफल प्रयोग सहकारी समितियों के सहयोग से किया जाएगा। जैविक खेती में नवाचार दिखाने वाले किसानों की ब्रांडिंग से लेकर मार्केटिंग की व्यवस्था की जाएगी। जैविक उत्पादों की खरीद और बेहतर मूल्य से लेकर बाजार उपलब्ध कराने की कार्ययोजना बनायी जाएगी। सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को जैविक खेती में नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। ऐसे उत्पादों को पंजीकरण कराने से लेकर प्रमाणन की व्यवस्था भी होगी। गुजरात के भरूच जैसे क्षेत्रों में केले के तने से रेशा और वर्मी कम्पोस्ट जैसे जैविक उत्पाद बनाकर आय बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। गुजरात में अमूल जैसी सफल सहकारी संस्थाओं की कार्यशैली ने वहां ग्रामीण आजीविका को नई ताकत दी है। यह कार्य बिहार में भी सहकारी समितियों से होगा।

तैयारी

- **अगले माह से सहकारी समितियों के 50-50 लोगों की टीम गुजरात के दौरे करेगी**
- **स्टडी रिपोर्ट के आधार पर सरकार बनाएगी कार्ययोजना, रोजगार सृजन भी**

स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार के अवसर

सहकारिता विभाग ग्रामीण इलाकों में इको टूरिज्म को बढ़ावा देकर स्थानीय युवकों को रोजगार के अवसर देने पर भी काम कर रहा है। इसके लिए टैक्सी सर्विस स्कीम भी लाच करने की योजना बन रही है। इससे स्थानीय लोगों को सीधे रोजगार प्रदान करने में मदद मिलेगी। गुजरात में महिलाओं द्वारा संचालित दुग्ध समितियों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यही प्रयोग बिहार के सभी गांवों में महिलाओं द्वारा दुग्ध समितियों के संचालन में होगा। हर गांव में दुग्ध सहकारी समिति गठित की जा रही है। प्रोटीन कंसन्ट्रेट पाउडर प्लांट जैसी नई इकाइयां लगायी जाएंगी।

तकनीक पर जोर

डिजिटल तकनीक का उपयोग बढ़ाने से भी सहकारी समितियों को ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा। इससे किसानों को सीधे लाभ मिलेगा और बिचौलियों की भूमिका कम होगी। सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता लाने पर भी जोर दिया जाएगा, ताकि सहकारी समितियों के सदस्य किसानों का भरोसा और मजबूत हो। सरकार का लक्ष्य है कि सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी की जाए। इसके लिए आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रबंधन और नई योजनाओं को लागू करने पर फोकस किया जा रहा है।